आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बृहस्पतिवार 07.05.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने कहा – देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी।
- ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने पर जोर दिया।
- प्रदेश सरकार बदरीनाथ धाम को स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करेगी।
- और, अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर–मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही ळें संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा

ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया है। रुद्रप्रयाग में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, खादी ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

इस दौरान श्री चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वरोजगार आधारित योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी उत्पादों को 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बैठक में उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की और प्रदेश का सर्वेश्रेष्ठ जिला बनाने पर जोर दिया।

जनगणना

उत्तराखण्ड शासन ने आगामी जनगणना–2027 के सुचारु और सफल संचालन को लेकर दिशा–निर्देश जारी कर दिए हैं। जनगणना सचिव दीपक कुमार ने जनसामान्य से जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग करने तथा पूछे गए सभी प्रश्नों के सटीक और स्पष्ट उत्तर देने की अपेक्षा की है।

उन्होंने कहा कि जनगणना देश का एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक सांख्यिकीय स्रोत है, जिसके माध्यम से मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, संपत्तियां, जनसांख्यिकी विवरण, साक्षरता, धर्म, आर्थिक गतिविधियों और प्रवासन से संबंधित जानकारी ग्राम और नगर स्तर तक उपलब्ध होती है।

उन्होंने बताया कि जनगणना अधिकारी को अपने निर्धारित क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। प्रत्येक नागरिक का यह वैधानिक दायित्व होगा कि वह अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही उत्तर उपलब्ध कराए।

हालांकि, किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की किसी महिला सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही, कोई महिला अपने पति, मृत पति अथवा ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगी, जिसका नाम बताना सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध माना जाता हो।

स्प्रिचुअल हिल टाउन

प्रदेश सरकार बदरीनाथ धाम को स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बद्रीनारायण चौक को एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं और आकर्षक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध होंगे। पेश है। योजना के अंतर्गत बदरीनाथ धाम में आईएसबीटी वॉल पर स्थानीय कला और धार्मिक विषयों पर आधारित भित्ति चित्रों के माध्यम से क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। वसुधा वाटिका कलाकृति के जरिए प्रकृति, आध्यात्मिकता और उत्तराखंड की पारंपरिक कला को समाहित करते हुए आकर्षक लैंडस्केप तैयार किए जाएंगे।

मास्टर प्लान में भगवान विष्णु से जुड़े प्रतीकों को भी प्रमुखता दी गई है, जिनमें पाञ्चजन्य शंख, कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र और वैकुंठ द्वार जैसी भव्य कलाकृतियों का निर्माण किया जाएगा। ये न केवल धार्मिक महत्व को दर्शाएंगी, बल्कि श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी बनेंगी। इसके साथ ही शेषनेत्र कलाकृति और पंचतत्व थीम पर आधारित संरचनाएं आध्यात्मिक ऊर्जा और भारतीय दर्शन को प्रदर्शित करेंगी। योजना में भगवान राम और भगवान कृष्ण से संबंधित रामायण और महाभारत कालीन प्रतीकों को भी शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत

अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में वादों का निस्तारण आपसी सुलह–समझौते के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने वादकारियों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे लोक अदालत की तिथि से एक दिन पहले तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

यातायात दबाव

देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। आवास विभाग की बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा अंडरग्राउंड पार्किंग निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई।

योजना के अनुसार परेड ग्राउंड और गांधी पार्क के मध्य लगभग 6 हजार 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस पार्किंग में करीब 3 हजार 90 वाहनों को खड़ा करने की क्षमता होगी।

परियोजना के क्रियान्वयन से राजपुर रोड, ऐस्ले हॉल, सचिवालय स्थित सुभाष रोड और लैंसडाउन चौक के बीच सड़क किनारे खड़े वाहनों को व्यवस्थित पार्किंग सुविधा मिल सकेगी। इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है।

पर्यटन मसूरी

मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ और बैरियरों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत देने के लिए नगर पालिका ने पर्यटक शुल्क वसूली व्यवस्था को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। 'पहाड़ों की रानी' के नाम से प्रसिद्ध मसूरी में जल्द ही प्रमुख बैरियरों पर फास्टैग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे वाहन बिना रुके शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

नगर पालिका परिषद मसूरी ने इस परियोजना के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी के साथ अनुबंध किया है। नई व्यवस्था माल रोड स्थित पिक्चर पैलेस बैरियर, लाइब्रेरी बैरियर और कोलुखेत टोल बैरियर पर लागू की जाएगी।

पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान प्रणाली से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शहर के प्रवेश मार्गों पर जाम की समस्या में भी कमी आएगी। प्रशासन का मानना है कि यह पहल मसूरी में स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।